हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 108 लखनऊ, गुरुवार 04 दिसम्बर 2025 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

विश्व दिव्यांग दिवस: मुख्यमंत्री ने किया राज्यस्तरीय कार्यक्रम का किया उद्घाटन

500 दिव्यांगजनों को बांटे ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरण
18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का लिया गया निर्णय
दिव्यांग पेंशन 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए, योगी सरकार का बड़ा निर्णय

लखनऊ ब्यूरो

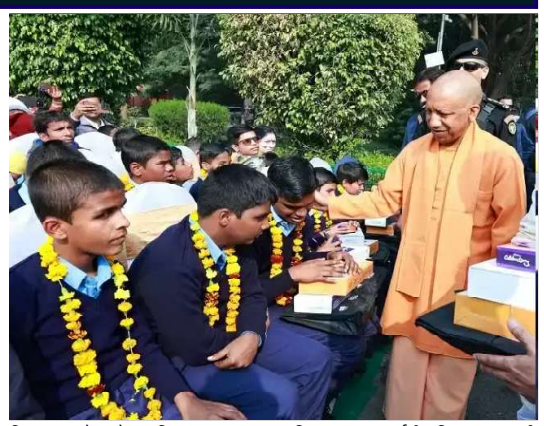

लखनऊ। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं एवं सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने 500 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल एवं विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए, दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र–छात्राओं को टैबलेट व प्रमाण–पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग के कक्षा–9 से 12 तक के 5,33,285 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण–पत्र तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण–पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के समग्र कल्याण, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DRC) की स्थापना की जाएगी, जिससे सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग और थेरेपी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने, सहायक उपकरणों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने तथा विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों को 35,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री कश्यप ने कहा कि विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों से आए 500

दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए और विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत 36 मेधावी छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि 03 से 05 दिसम्बर 2025 तक आयोजित "दिव्य कला प्रदर्शनी" दिव्यांगजन की कलात्मक, तकनीकी, व्यावसायिक एवं उद्यमशील क्षमताओं का अनूठा प्रदर्शन करेगी, जिसमें दिव्यांग कलाकारों और बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

मानवीय आधार पर राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत वापसी की दी मंजूरी

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती महिला और उसके आठ साल के बच्चे को 'मानवीय आधार' पर भारत में प्रवेश की बुधवार को अनुमति दे दी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग बच्चे की देखभाल करने और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सुनाली खातून को हर संभव चिकित्सा सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान पर गौर किया कि सक्षम प्राधिकारी ने मानवीय आधार पर महिला और उसके बच्चे को देश में प्रवेश देने के लिए सहमति जता दी है और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अंततः उन्हें दिल्ली वापस लाया जाए, जहां से उन्हें पकड़कर बांग्लादेश भेजा गया था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने अदालत से आग्रह किया कि बांग्लादेश में सुनाली के पति समेत अन्य लोग भी लोग हैं, जिन्हें भारत वापस लाने की आवश्यकता है। इसके लिए मेहता केंद्र से आगे के निर्देश ले सकते हैं। मेहता ने कहा कि वह उनके भारतीय नागरिक होने के दावे को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ मानवीय आधार पर उस महिला और उसके बच्चे को भारत में आने की अनुमति दे रही है।

राष्ट्रपति बोलीं- स्वावलंबन से मजबूत होती है राष्ट्रीय सुरक्षा; केरल के तट पर नौसेना ने दिखाई

एजेंसी

तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय नौसेना स्वदेशी तकनीक के विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत को

शविकसित भारतश बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। नौसेना ने समुद्र, हवा और सतह पर किया प्रदर्शन इस मौके पर भारतीय नौसेना ने समुद्र, हवा और सतह, तीनों मोर्चों पर अपनी क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 19 बड़े युद्धपोत, जिनमें स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत भी शामिल था, एक पनडुब्बी, चार फास्ट इंटरवेशन बोट्स और 32 विमान, लड़ाकू जेट, निगरानी विमान और हेलिकॉप्टर शामिल थे। एमएच–60आर हेलिकॉप्टर ने दी राष्ट्रपति को सलामी नौसेना ने इस दौरान अपने आधुनिक युद्धपोतों और अत्याधुनिक हथियारों की झलक जनता को दिखाई। इस प्रदर्शन में आईएनएस कोलकाता, आईएनएस इंफाल और आईएनएस उदयगिरी जैसी ताकतवर युद्धपोतों ने आकर्षण बढ़ाया। आईएनएस विक्रांत पर मौजूद मिग–29 विमान के उड़ान भरते ही जनता की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आसमान में एमएच–60आर हेलिकॉप्टर ने फ्लेयर्स छोड़कर राष्ट्रपति को सलामी दी, वहीं डॉर्नियर विमानों ने बॉम्ब बर्स्ट फॉर्मेशन में उड़ान भरकर रोमांच बढ़ाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने की नौसेना की सराहना इस कार्यक्रम के दौरान नौसेना के मार्कोस कमांडो ने समुद्र में एक जहाज पर समुद्री डकैती और बंधक बचाव अभियान का लाइव प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नौसेना की सराहना करते हुए कहा, श्हम सभी को मिलकर समुद्र की रक्षा, जहाज निर्माण को बढ़ावा, नाविकों का सम्मान और भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा को आगे बढ़ाना होगा।श उन्होंने भारतीय नौसेना के सदैव विजयी रहने की कामना भी की। इससे पहले राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर और आईएनएस कोलकाता से तोपों की सलामी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रदर्शन आम जनता के लिए नौसेना की क्षमता और तैयारी को नजदीक से देखने का एक बड़ा अवसर था।

मायावती ने लिया बड़ा फैसला, कहा- नहीं करेंगे स्मारकों के दर्शन

सुरक्षा के चलते आमजन को अब नहीं होगी दिक्कत

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि वह अब प्रमुख समाज सुधारकों की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें समर्पित बड़े स्मारकों पर नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था से आम लोगों को असुविधा होती है। मायावती ने 'एक्स' पर एक विस्तृत पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के चार कार्यकाल के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, डॉ. बी. आर. आंबेडकर और कांशीराम जैसे महान समाज सुधारकों और प्रतीकों का

सम्मान किया गया, जिन्हें ''जातिवादी पार्टियों'' की सरकारों में अक्सर ''नजरअंदाज'' किया जाता था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बसपा सरकार ने इन नेताओं के नाम पर कई प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं और लखनऊ तथा गौतम बुद्ध नगर में भव्य स्मारक, पार्क व स्मृति स्थल बनाए, जो अब उनके समर्थकों के लिए ''तीर्थस्थलों'' में बदल गए हैं और उनकी जयंती व पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। मायावती ने कहा कि इन स्थलों पर उनकी यात्राओं से भारी सुरक्षा प्रबंधों के कारण लोगों को असुविधा होती है।

उन्होंने कहा, ''अनुभव यह दिखाता है कि मेरे दौरे के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था से लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक मैं वहां से चली नहीं जाती, लोगों को मुख्य स्थल से काफी दूर रोक दिया जाता है।'' बसपा प्रमुख ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए वह अब अपने आवास या पार्टी कार्यालय में इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि ही देंगी, स्मारकों पर जाकर नहीं। उन्होंने कहा कि छह दिसंबर को डॉ. बी. आर. आंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर) के कार्यकर्ता व समर्थक लखनऊ में स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ी संख्या में जुटेंगे, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के लोग नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक समानता और आत्मसम्मान के आंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे, ताकि बसपा ''सत्ता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सके'' और इन महापुरुषों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके।

संक्षिप्त समाचार

केंद्र की सख्त चेतावनी, दिल्ली की जहरीली हवा पर लगाम, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर तलवार लटकी

एजेंसी

नयी दिल्ली। केंद्र ने लगातार खतरनाक वायु गुणवत्ता के बीच बुधवार को दिल्ली–एनसीआर के अधिकारियों को 31 दिसंबर तक वास्तविक समय में उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित न करने पर अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को इस महीने के भीतर अपनी 2026 की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिये गये। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष वीर विक्रम यादव ने कहा कि दिल्ली–एनसीआर में 2,254 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों ने अभी तक अपने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) को सीपीसीबी सर्वर से स्थापित और कनेक्ट नहीं किया है। यादव ने कहा, ''31 दिसंबर की समय सीमा को पूरा नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ उन्हें बंद करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।''

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दहेज में मिला पैसा और सोना वापस पाने का अधिकार

एजेंसी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि तलाक पर अधिकारों का संरक्षण

एक्ट, 1986 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पिता से मिले दहेज का पैसा और सोना वापस पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तलाकशुदा महिला रौशनारा बेगम के मामले में सुनाया, जिन्होंने अपने पहले पति से दहेज के रूप में प्राप्त सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।रौशनारा बेगम का निकाह 2005 में हुआ था और 2011 में उनका तलाक हो गया था। निकाह के समय महिला के पिता ने दामाद को सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने के गहने दिए थे, जिसकी जानकारी निकाह रजिस्टर में दर्ज थी। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने काजी और महिला के पिता के बयानों में असंगति का हवाला देते हुए महिला का दावा खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि निकाह के समय मिले धन और गहनों का संबंध महिला की सुरक्षा और गरिमा से है। अदालत ने इस कानून की व्याख्या महिला के समानता और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों के आधार पर की।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का सोना बरामद, तस्कर गिरफ्तार

एजेंसी

कोलकाता। बीएसएफ को दक्षिण बंगाल सीमांत पर बड़ी कामयाबी मिली। बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल

के नदिया जिले में भारत–बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा एक बांग्लादेशी तस्कर को उस समय गिरफ्तार किया जब वह अवैध सोने के बिस्कुटों के साथ सीमा पार करने का प्रयास कर रहा था। जब्त किए गए सोने के बिस्कुटों का कुल वजन 2354.73 ग्राम और अनुमानित कीमत 3,05,99,716 आंकी गई है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी और डीआईजी नीलोत्पल पाण्डेय के मुताबिक मंगलवार को 32वीं वाहिनी सीमाचौकी तुंगी को गुप्त सूचना मिली कि पर कुछ बांग्लादेशी तस्कर अवैध सोने की तस्करी की फिराक में हैं। जवान तुरंत सतर्क हो गए। शाम करीब 5 बजे दो संदिग्ध व्यक्ति जलकुंभी की आड़ लेकर झील के रास्ते बांग्लादेश की तरफ से भारत की सीमा की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। सतर्क जवानों ने दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को चेतावनी दी और उनको घेरने का प्रयास किया। एक तस्कर को जवानों ने पकड़ लिया जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा।

इसके बाद आस पास के इलाके की गहन तलाशी ली गई। मौके से कुछ पैकेट बरामद हुए, जिसकी जांच करने पर उसके अंदर से सोने के 20 बिस्कुट बरामद हुए। पकड़े गए तस्कर को आगे की पूछताछ के लिए सीमा चौकी तुंगी लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान तस्कर ने बताया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है और कुछ समय से सीमा पार अवैध गतिविधियों मे संलिप्त है। उसने बताया कि उसे यह सोना सीमा पार किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना था, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे देने का वादा किया गया था, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया और वे अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तार किये गए तस्कर को जब्त सोने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है।

कांग्रेस का संसद में हंगामा, नई लेबर कोड से मजदूरों की नौकरी पर संकट, खरगे का मोदी सरकार पर तीखा हमला

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को मोदी सरकार पर ''मजदूर विरोधी और पूंजीपति समर्थक'' होने का आरोप लगाया और दावा किया कि हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के कारण श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा एवं स्थायित्व खतरे में पड़ गया है। खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''मोदी सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक है। विपक्षी दलों ने आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, नयी लागू की गई श्रम संहिताओं पर कड़ी आपत्ति जताई। नयी संहिताओं में कुछ गंभीर चिंताएं हैं।''उन्होंने दावा किया कि छंटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि भारत में 80 प्रतिशत से अधिक कारखाने अब सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को नौकरी से हटा सकते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी। खरगे ने कहा कि तय समयसीमा वाले रोजगार के विस्तार से कई स्थायी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तथा कंपनियां अब दीर्घकालिक लाभ से बचते हुए, अल्पकालिक अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रख सकती हैं।

पीएम मोदी सरकार के पास जाति जनगणना पर ठोस रूपरेखा नहीं, बहुजनों के साथ विश्वासघात : राहुल

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निचले सदन में अपने लिखित प्रश्न का सरकार द्वारा दिए गए उत्तर का हवाला देते हुए बुधवार को दावा किया कि मोदी सरकार के पास जाति जनगणना को लेकर कोई ठोस रूपरेखा और योजना नहीं है और यह देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा था। उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद।'' उन्होंने दावा किया, ''दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है।''राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में लिखित प्रश्न किया था, '' दशकीय जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रक्रियात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समयसीमा क्या है, जिसमें प्रश्नों की तैयारी, कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है? क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार अलग–अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है।

जनसंपर्क और ज़मीनी विरोध पर ज़ोर : PM Modi ने बंगाल बीजेपी सांसदों को दिया चुनावी सफलता का सीक्रेट फॉर्मूला

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राज्य के मौजूदा हालात में स्पष्ट संवाद और जन–सम्पर्क की ज़रूरत है, और पार्टी को ज़मीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। सूत्रों के अनुसार, 2026 की तैयारियों के संबंध में, प्रधानमंत्री ने सांसदों से विस्तृत प्रस्तुतियाँ तैयार

करने और आगामी राजनीतिक योजना व लामबंदी के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री के एक करीबी सूत्र के अनुसार, मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एसआईआर को ज़्यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए और यह संदेश ज़मीनी स्तर तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया में स्पष्टता और दक्षता पर ज़ोर देते हुए कहा कि एसआईआर अभियान को सरल और पारदर्शी रखें। इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाए और जो योग्य नहीं हैं उन्हें हटाया जाए। उन्होंने सांसदों से 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में पार्टी को केंद्रित और आश्वस्त बनाए रखने का भी आह्वान किया। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की ताकत का लाभ उठाने और वर्षों से बनी गति को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से कहा कि सांसद खगेन मुर्मू पर हमले जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया जाना चाहिए ताकि लोग टीएमसी से जुड़ी हिंसा को समझ सकें। कल, 3 दिसंबर को, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यालय में संसद भवन में असम के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की। बैठक के दौरान, उन्होंने उनकी संसदीय गतिविधियों पर चर्चा की और उन्हें जनता के बीच अधिक सक्रिय होने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ–साथ जनभागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

संपादकीय

एसआईआर पर नया विवाद

24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर का आदेश) दिया था, जो शुरुआत से विवादों में बना रहा। इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं विपक्ष ने प्रकट कीं, जिनमें से कई सही भी साबित हुईं। लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष की चिंताओं का कोई समाधान नहीं किया। वहीं सत्तारुढ़ भाजपा ने भी लगातार एसआईआर को जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग का बचाव किया। भाजपा ने तो यहां तक दावा किया कि विपक्ष घुसपैठियों का साथ दे रहा है, इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने आज तक यह नहीं बताया है कि उसे कितने घुसपैठिए मतदाता के तौर पर मिले हैं। बहरहाल, एसआईआर पर उठ रहे कई तरह के सवालों के बीच अब एक बड़ा खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। जिसके बाद चुनाव आयोग का फैसला और नीयत दोनों पर तत्काल सफाई पेश किए जाने की जरूरत है। क्योंकि एसआईआर में सबसे बड़ी चिंता यही थी कि नागरिकों से उनके मतदान का हक छीना जा रहा है। यह चिंता इस खुलासे के बाद और गहरा गई है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने एसआईआर के आदेश के मसौदे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी को हटाने का खुलासा किया है। श्री संधु ने आदेश के ड्राफ्ट संस्करण में एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी। जो हटा दी गई है। चुनाव आयुक्त संधु ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था– श्यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाताध्नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए।यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब एसआईआर के लिए वैध दस्तावेज की सूची जारी की गई, तो सबसे ज्यादा तकलीफ में गरीब ही आए। बिहार से ऐसी ढेरों खबरें आईं, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल भी पूछा गया कि आधार को दस्तावेज लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। दो बार की मौखिक सलाह के बाद तीसरी बार अदालत को भी आधार शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को सख्त लहजे में कहा गया। अब श्री संधु की टिप्पणी के बाद समझ आ रहा है कि चुनाव आयोग में भी नागरिकता बचाने पर चिंता व्यक्त की जा रही थी। ये और बात है कि उस चिंता को जाहिर नहीं होने दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे किसका दबाव था, क्या चुनाव आयुक्तों में मतभेद है, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने साथी चुनाव आयुक्त द्वारा व्यक्त की गई चिंता की उपेक्षा की, ऐसे कई सवाल इस खुलासे के बाद उठ रहे हैं।गौरतलब है कि अंतिम आदेश में श्री संधु की टिप्पणी को हटा दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाद में उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा देखे गए ड्राफ्ट आदेश के पैराग्राफ 2.5 और 2.6 में एसआईआर को स्पष्ट रूप से नागरिकता अधिनियम से जोड़ा गया था और अधिनियम में हुए बदलाव को इस प्रक्रिया का औचित्य बताया गया था। ड्राफ्ट आदेश में लिखा था कि श्आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम, 1955 (श्नागरिकता अधिनियमश) के अनुसार केवल नागरिकों के ही नाम मतदाता सूची में शामिल हों। नागरिकता अधिनियम में 2004 में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था और उसके बाद देशभर में कोई गहन संशोधन नहीं किया गया था।लेकिन अंतिम आदेश में नागरिकता अधिनियम और 2003 में पारित तथा 2004 से लागू संशोधन के सभी संदर्भ हटा दिए गए। उसकी जगह लिखा गया– श्चूंकि संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित मूलभूत शर्तों में से एक यह है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। फलस्वरूप, आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि केवल नागरिक ही...श। यह पैराग्राफ अचानक बीच में ही खत्म हो जाता है, वाक्य सेमिकोलन के बाद अधूरा रह जाता है।24 जून से अब तक चुनाव आयोग ने इस अध्ूरी लाइन पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर वो लाइन अधूरी क्यों है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसने 28 नवंबर को आयोग के प्रवक्ता से दोनों आदेशों में हुए बदलाव के बारे में पूछा था, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं मिली। वहीं आयुक्त संधु से भी उनकी टिप्पणी के बारे में और यह भी पूछा गया कि क्या उनकी चिंताओं का समाधान किया गया, लेकिन वे भी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। यह अजीब बात है कि आयुक्त संधु ने नागरिकता के जिस बिंदु पर चिंता जाहिर की थी, उसका नाम लिए बिना ही उसे अंतिम आदेश के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया। 24 जून के आदेश में लिखा हैरू श्चूंकि यह गहन संशोधन है, इसलिए यदि 25 जुलाई 2024 से पहले गणना फॉर्म जमा नहीं किया गया तो मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकेगा। फिर भी, सीईओध्डीईओध्ईआरओध्बीएलओ यह भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाता, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न हों और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिसमें स्वयंसेवकों की तैनाती भी शामिल है।श गौर कीजिए कि एसएस संधु की टिप्पणी से श्नागरिकश शब्द का उल्लेख यहां पूरी तरह हटा दिया गया है।

राशिफल

मेष :– परिजनो व मित्रों का सनिध्य से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य–पेशे में कोई अवरोधित कार्य सार्थक होने के आसार है। मांगलिक एव सास्कृतिक आयोजनों में सम्मलित होंगे। महत्वपूर्ण कार्य में आलस्य ना करे।

बृषभ :– परिश्रम द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। समय बड़ा मूल्यवान है। अतः इसे व्यर्थ न गंवायें। किसी नए सम्वेदना का प्रभाव नए रिश्ते को जन्म देगा। अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा।

मिथुन :– परम्पराओ व संस्कारों कें प्रति आस्था बढ़ेगी। निर्थक हीनभाव एवं कुछ साथ के प्रगतिशील व्यक्तियों से ईष्या भाव ठीक नही। अस्थिर मन लक्ष्य के प्रति केन्द्रित होने मे असमर्थ होगा।

कर्क :– किसी महत्वपूर्ण कार्य वश घर से दूर रहना अरुचिकर लगेगा। आपका मिलनसारिता के कारण सम्बन्धो का बिस्तार होगा। कमजोर मनोबल के कारण लक्ष्य के प्रति दृढ़ता का अभाव रहेगा।

सिंह :– किसी महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ी कठिनाई का अभास होगा। संवेदनशील मन पूरानी मर्मस्पर्शी घटनाओं से ओत–प्रात होगा। परिवारिक दायित्वों को समयानुकूल पूर्ति हेतु मन चिन्तित होगा।

कन्या :– प्रयासरत क्षेत्रों में अवरोध तथा दाम्पत्य जीवन में कष्ट संभव। परन्तु ईरीय आस्था हर परीस्थिती पर बिजय प्राप्त करेंगे। धैर्यपूर्वक महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करें।

तुला :– घर–परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। पिछले दिनों उत्पन्न को व्यवसायिक अवरोध के हल ढूंढने में मन केद्रित होगा। किसी पुराने मित्र की मध्यस्तता से बिगड़े हुए सम्बन्धो में सुधार होगा।

वृश्चिक :– मनोवांछित सफलता न मिलने से उत्साह में कमी होगी। भौतिक चका–चौंद से प्रभावित मन अभाव की अनुभूति से दुखित होगा। धैर्यहीनता व परिवर्तनशीलता लक्ष्य से दिग्भ्रमित करेगा।

धनु :– आपकी महत्वाकांक्षाए सफलता की राह पर संघर्ष हेतु प्रेरित करेंगी। अच्छी भावनाऐं आपके मकसद सफलता दिलाऐंगी। कार्य क्षेत्र में अपनें बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाऐंगे।

मकर :– कुछ नये सम्बन्द बनेगें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद सम्भव। कर्तव्य व जिम्मेदारियों से घिरा मन अपनी कल्पनिक आकांक्षाओं से समझौता करने में सक्षम होगा। किसी नई दिशा में रुचि बढ़ेगी।

कुंभ :– मन को खराब विचारो से दूर रखते हुए अच्छे कायरे में केन्द्रित करें। नई स्थितियाँ आप मे नई प्रतिभाओं का संचार करेगा। कार्यकुशलता व प्रतिभा का जौहर बिखेरेंगे।

मीन :– अपनी वाणी पर नियंतण्ररखते हुए सम्बन्धों को मधुर बनाने की चेष्टा करें। प्रतिभा व आत्मबल कुछ महत्वपूर्ण सफलताओ के प्रति आशान्वित करेगा। आर्थिक लाभ के आसार हैं।

संचार साथी ऐप : सुरक्षा का दावा या निगरानी का हथियार?

बृजेश चतुर्वेदी

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा लाए गए संचार साथी ऐप और उसके प्रमुख फीचर चक्षु पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जहाँ एक ओर सरकार इसे डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर, ऐप की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारियाँ और इसकी अनिवार्यता पर DoT का निर्देश इसकी भूमिका को सुरक्षा उपकरण से कहीं अधिक राज्य–प्रायोजित निगरानी (State–Sponsored Surveillance) के रूप में संदेह के घेरे में ला खड़ा करते हैं। यह विवाद तब और गहरा गया जब क्वज ने स्मार्टफोन निर्माताओं से संचार साथी ऐप को सभी नए उपकरणों में प्री–इंस्टॉल करने और पुराने फोनों में भी अपडेट के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए कहा, साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया कि उपयोगकर्ता इसे डिलीट न कर पाएँ।

चक्षु की सीमाएँ : सुरक्षा का खोखला दावा

संचार साथी ऐप का मुख्य आकर्षण श्चक्षुश फीचर है, जिसे फ्रॉड पहचानने का टूल कहा जा रहा है। हालाँकि, इसकी आधिकारिक वेबसाइट यह स्पष्ट करती है कि:

वित्तीय ठगी या साइबर अपराध की शिकायत के लिए चक्षु एक सुविधा नहीं है।

यदि किसी नागरिक का पैसा चला गया है या वह साइबर क्राइम का शिकार हुआ है, तो उसे अनिवार्य रूप से हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in वेबसाइट पर रिपोर्ट करना होगा।

इससे स्पष्ट है कि चक्षु केवल संभावित धोखाधड़ी वाले कॉल, SMS या WhatsApp संदेशों की रिपोर्टिंग के लिए है। असली अपराध होने, या वित्तीय नुकसान हो जाने पर, ऐप की भूमिका लगभग शून्य है। ऐसे में, यह बड़ा सवाल उठता है कि यदि यह ऐप साइबर सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलूकृआर्थिक नुकसानकृमें नागरिक की मदद नहीं कर सकता, तो 100 करोड़ मोबाइल में इसे जबरन डलवाने का उद्देश्य सुरक्षा से अधिक क्या है? विपक्ष का तर्क है कि यह मंशा जासूसी के सिवा कुछ और नहीं हो सकती।

जरूरत से ज्यादा परमीशन और प्राइवेसी का हनन

यह संदेह और भी पुख्ता हो जाता है जब हम ऐप द्वारा माँगी जा रही अनुमतियों (Permissions) की सूची पर गौर करते हैं। संचार साथी कई खतरनाक (Dangerous) परमीशन की मांग करता है, जिनमें शामिल हैं:

android.permission.SEND–SMS: SMS भेजने की अनुमति, जिससे वित्तीय लागत आ सकती है।

android.permission.READ–SMS: फ़ोन पर स्टोर किए गएँ डे या डडे पढ़ने की अनुमति, जिससे गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है।

android.permission.READ–CALL-LOG: उपयोगकर्ता के कॉल लॉग तक पहुँच।

android.permission.READ-PHONE–STATE: फ़ोन नंबर, सीरियल नंबर और कॉल की स्थिति जैसी जानकारी तक पहुँच।

android.permission.WRITE–EXTERNAL–STORAGE: बाहरी स्टोरेज की सामग्री को पढ़ने, संशोधित करने या हटाने की अनुमति।

किसी भी ऐप को प्री–इंस्टॉल करने और उसे डिलीट न करने देने की ज़िद, साथ ही इतने व्यापक डेटा तक पहुँच की मांग करना, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार केवल खोए हुए फोन को खोजने या फ्रॉड रोकने से अधिक, नागरिकों की निजता में घुसपैठ करने में दिलचस्पी रखती है। आलोचकों का तर्क है कि एक ऐसा ऐप जो कैमरा, माइक, लोकेशन, कीबोर्ड और कॉल लॉग तक आधिकारिक तौर पर सुनने–देखने लगे, वह नियंत्रण स्थापित करने का एक माध्यम बन जाता है।

उपयोगकर्ता रेटिंग : सीमित प्रभावशीलता की कहानी

उपलब्ध डेटा के अनुसार, ऐप को 14,826 समीक्षाओं के विश्लेषण पर औसत 4.4 की रेटिंग मिली है, जिसमें 85% उपयोगकर्ता संतुष्ट हैं। हालाँकि, समीक्षाओं में 11% (1636) गंभीर समस्याएँ (Issues Reported) भी दर्ज की गई हैं। संतुष्टि की उच्च रेटिंग के बावजूद, ऐप की मुख्य सीमाएँकृजैसे कि गंभीर साइबर अपराधों के लिए अक्षमताकृ बनी हुई हैं। समीक्षा डेटा यह पुष्टि करता है कि ऐप कुछ बुनियादी स्तर की सहायता प्रदान कर सकता है (जैसे खोए हुए फोन को ट्रैक करना), लेकिन समीक्षाओं की मात्रा में वृद्धि (विशेषकर नवंबर 2025 के अंत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि) और 11% गंभीर रिपोर्ट किए गए मुद्दे, इसकी पूर्ण प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं।

निरंकुशता की राह पर भारत?

आलोचक इस कदम की तुलना रूस के निरंकुश शासन से कर रहे हैं, जहाँ 1 सितंबर 2025 को सरकार नियंत्रित मैसेजिंग मैनेजमेंट ऐप MAX को प्री–इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया था। रूस में यह ऐप सुरक्षा एजेंसी थ्ठ को लोगों के कॉल, लोकेशन, टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया डेटा तक पहुँच प्रदान करता है। भारत में भी, निरंकुश सत्ता के आरोप के बीच, यह कदम श्जासूसीश की आशंकाओं को जन्म देता है। पहले से ही NATGRID जैसे डेटाबेस की समीक्षा और हाल ही में संशोधित DPDP एक्ट के नियम 23, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी सेवा प्रदाता से सारा डेटा मांगने की शक्ति देते हैं, ने इन आशंकाओं को और बल दिया है। संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने का निर्णय लोकतंत्र में एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। यदि ऐप वास्तविक साइबर सुरक्षा में सीमित भूमिका निभाता है, लेकिन गोपनीयता के लिए खतरनाक अनुमतियाँ मांगता है, और उसे डिलीट करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो यह स्पष्ट है कि इसका मकसद नागरिक सुरक्षा से कहीं अधिक सार्वभौमिक निगरानी है। एक लोकतांत्रिक देश में, सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने के लिए जबरन ऐसा उपकरण डालना, नागरिकों की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार पर एक सीधा हमला है। सरकार को या तो अपनी मंशा साफ करनी होगी, या इस निरंकुश निर्देश को तुरंत वापस लेना होगा।

2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 विश्व-ओलंपिक : भारत की सांस्कृतिक-शक्ति रणनीति का अवसर, जोखिम और भविष्य

वैश्विक प्रतिष्ठा से लेकर आर्थिक बोझ तक-विशाल खेल आयोजनों की मेजबानी में भारत की रणनीतिक चुनौती और संभावनाएँ

–डॉ सत्यवान सौरभ

सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सन 2036 के विश्व–ओलंपिक प्रस्ताव का निर्णायक "अग्रदूत" हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक–शक्ति (सॉफ्ट पावर) को नई ऊँचाई दे सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कमी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा सकती है। विशाल खेल आयोजन किसी भी राष्ट्र के लिए मात्र खेल–प्रतियोगिताएँ नहीं होते, बल्कि वे उस देश की राजनैतिक इच्छा–शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य, सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक परिपक्वता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी होते हैं। आधुनिक समय में खेल कूटनीति एक प्रकार की सांस्कृतिक–शक्ति बन चुकी हैकृऐसी शक्ति जो बिना किसी सैन्य बल के, विश्व समुदाय को अपने अनुकूल प्रभावित कर सकती है। भारत लंबे समय से विश्व–स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा के विविध आयामों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता आया है, और सन 2036 के विश्व–ओलंपिक आयोजन की महत्वाकांक्षा इसी दिशा का अगला स्वाभाविक चरण है। परंतु ओलंपिक जैसे विराट आयोजन से पहले सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को भारत एक प्रकार के "पूर्वाभ्यास", "पूर्व–ओलंपिक नमूने" और "वैश्विक विश्वास की परीक्षा" के रूप में देख रहा है। यह रणनीति जितनी आकर्षक संभावनाएँ प्रदान करती है, उतनी ही गंभीर आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में इस प्रकार के आयोजनों की तैयारी केवल खेल मंत्रालय का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर निकायों, सुरक्षा संस्थाओं, निजी क्षेत्र, तकनीकी विशेषज्ञों, खेल संघों और व्यापक समाजकृसभी का संयुक्त प्रयास मांगती है। यदि भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित कर लेता है, तो यह विश्व स्तर पर यह संदेश जाएगा कि देश 2036 के विश्व–ओलंपिक जैसे महाकाय आयोजन को संभालने में सक्षम है। यही कारण है कि यह आयोजन भारत की विश्वसनीयता के लिए एक निर्णायक पड़ाव साबित हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी प्रेरणा सांस्कृतिक–शक्ति को सुदृढ़ करना है। आज वैश्विक राजनीति में खेल आयोजन एक सांस्कृतिक उत्सव से आगे बढ़कर राष्ट्र की क्षमताओं की खुली परीक्षा बन चुके हैं। राष्ट्र अपनी तकनीकी दक्षता, शहर–प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक समावेशन, पर्यावरण–जागरूकता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का विश्व मंच पर प्रदर्शन करते हैं। भारत यदि सन 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को उच्च स्तर पर सम्पन्न करता है, तो यह निःसंदेह भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। किन्तु इस प्रतिष्ठा की कीमत क्या होगी? यह वह कठिन प्रश्न है जिसे अनदेखा करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशाल खेल आयोजनों का सबसे विवादास्पद पहलू उनकी भारी आर्थिक लागत है। सन 2010 के राष्ट्रमंडल खेल अभी तक भारत की प्रशासनिक छवि पर एक दाग की तरह मौजूद हैंकृअत्यधिक खर्च, भ्रष्टाचार, समय पर कार्य न होना, और आयोजन स्थल की कमजोर गुणवत्ता ने भारत की छवि को काफी प्रभावित किया था। यदि वर्ष 2030 में फिर ऐसी ही कोई कमी सामने आती है, तो 2036 विश्व–ओलंपिक का सपना लगभग असंभव हो सकता है। इसलिए आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, बहु–स्तरीय जाँच, और जवाबदेही–व्यवस्था को आज से ही प्राथमिकता देनी होगी। इस सबके साथ–साथ 2030 का आयोजन भारत के लिए एक प्रयोगशाला भी सिद्ध हो सकता है। यह अवसर होगाकृशहरी अधोसंरचना, यातायात प्रबंधन, आपदा–प्रतिक्रिया, हरित ऊर्जा, जल–निकास प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं, सार्वजनिक सुरक्षा, और खेल विज्ञान को अंतरराष्ट्रीय मानक पर परखने का। इस स्तर के आयोजनों में क्षण भर की चूक भी बड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। इसलिए वर्ष 2030 का आयोजन भारत के लिए पूर्ण स्तर वाला अभ्यास सिद्ध हो सकता है, जिसमें न केवल खेल प्रबंधन बल्कि सम्पूर्ण शासन प्रणाली की परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त, शहरी प्रशासन को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। कोई भी विशाल खेल आयोजन केवल खेल–स्थल और खिलाड़ियों के निवास–स्थल तक सीमित नहीं रहता। यह पूरे नगर के परिवहन, मार्ग–संरचना, हवाई अड्डों की क्षमता, स्वच्छता प्रणाली, जल प्रबंधन, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारी, भीड़ नियंत्रण, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का तनाव परीक्षण बन जाता है। संभावित मेजबान नगरकृदिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या किसी बहु–नगर मॉडलकृ सभी पर भारी तैयारी का दबाव होगा। यह तैयारी अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि इससे नगरों का बुनियादी ढाँचा विश्व–स्तर पर पहुँच सकता है। चुनौती इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि यह निवेश केवल "दिखावे की अधोसंरचना" में बदल जाए, जो आयोजनदृउपरांत उपयोगहीन रह जाए। दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जहाँ खेल आयोजनों में बनाए गए स्टेडियम और भवन बाद में "मरे हुए ढाँचे" बन गए। भारत में भी यह समस्या पहले देखी जा चुकी है। इसलिए यह अनिवार्य है कि जो भी अवसंरचना बनाई जाए, वह आयोजन के बाद भी जनसाधारण, खेल प्रशिक्षण संस्थानों और नगर–विकास के लिए उपयोगी बनी रहे। भारत को पर्यटन, आतिथ्य, सांस्कृतिक प्रदर्शनों, कला एवं हस्तशिल्प, पारंपरिक संगीत, खानपान और जातीय विविधता जैसे क्षेत्रों में अपार लाभ प्राप्त होने की संभावना है। विश्व भर से लाखों दर्शक और प्रतिनिधि भारत आएँगे, जिससे सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, कृषि–आधारित उपभोग और सूक्ष्म उद्योगों को व्यापक लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भारत की अवधारणाकृजैसे पूर्णतः डिजिटल प्रवेश–प्रणाली, दूर–संवेदन सुरक्षा व्यवस्था, तेज संचार तंत्रकृविश्व के सामने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता का अत्यंत प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकती है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व–ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं की लागत बहुत भारी होती है। वर्तमान वैश्विक औसत के आधार पर यह लागत अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को एक वित्तीय प्रयोगशाला की तरह उपयोग किया जाए, जहाँ सार्वजनिक–निजी सहभागिता, सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, पर्यटन आधारित आय, और भागीदारी मॉडल जैसे उपायों की पहले से जाँच हो सके। यह देखा जा सके कि कौन–सा मॉडल भारत की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक स्थायी और सफल हो सकता है। परंतु आलोचना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि क्या भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को इतने बड़े आयोजनों पर अत्यधिक धन व्यय करना उचित है? क्या यह धन विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण खेलों, महिला खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल विज्ञान प्रयोगशालाओं और खेल अकादमियों जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत है। किसी भी खेल आयोजन का मूल उद्देश्य "राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की चमक" नहीं, बल्कि "राष्ट्रीय प्रतिभा का विकास" होना चाहिए। यदि आयोजन पर खर्च किए गए संसाधन जमीनी स्तर के खेल ढांचे से ध्यान हटाकर केवल भव्यता के निर्माण में लग जाएँ, तो यह राष्ट्रहित के प्रतिकूल होगा। इसके अतिरिक्त, यह आयोजन भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को भी नया आयाम प्रदान कर सकता है। भारत पहले से विश्व–दक्षिण समूह का अग्रणी प्रतिनिधि बन रहा है, और वैश्विक संस्थाओं में उसका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। ऐसे में सफल खेल मेजबानी भारत की बहुआयामी नेतृत्व क्षमता को और सुदृढ़ करेगी। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, सक्षम और विश्वस्तरीय आयोजक राष्ट्र बन चुका है। फिर भी अंतिम प्रश्न यही है–क्या भारत संस्थागत रूप से तैयार है? खेल संघों में आंतरिक राजनीति, पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, चयन प्रक्रियाओं की कमजोरी और प्रशासनिक अनिश्चितताकृये समस्याएँ अभी भी भारतीय खेल तंत्र को कमजोर बनाती हैं। यदि इन कमियों को दूर न किया गया तो 2030 और 2036 दोनों आयोजनों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अंततः, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए एक विशाल अवसर और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक–शक्ति, तकनीकी क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक दक्षता का विश्वव्यापी प्रदर्शन हो सकता है। यह 2036 विश्व–ओलंपिक के प्रस्ताव को निर्णायक रूप से सशक्त कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब भारत इसे केवल दिखावे का आयोजन न समझकर, इसे दीर्घकालिक राष्ट्रहित से जोड़कर देखे। यदि निवेश टिकाऊ हो, नीतियाँ पारदर्शी हों, प्रशासन उत्तरदायी हो, और अधोसंरचना जनता के उपयोग में रहे, तो यह दोनों आयोजन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय खोल सकते हैं। स्पष्ट है–2030 राष्ट्रमंडल खेल केवल "एक आयोजन" नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान, आर्थिक भविष्य और कूटनीतिक शक्ति का एक विस्तृत परीक्षण हैं। यह वह मोड़ है जहाँ सफलता भारत को विश्व खेल–पटल के केंद्र में स्थापित कर सकती है, और किसी भी प्रकार की विफलता इसे वर्षों पीछे धकेल सकती है। इसलिए भारत को इस यात्रा में संकल्प, सावधानी और दूरदृष्टि–तीनों का संतुलन बनाए रखना होगा।

बस्तर में हो रहा है सुनहरा सवेरा...

–नंदन जैन

जब किसी भी समस्या के समाधान के प्रति नेतृत्व की इच्छा शक्ति सच्चे अर्थों में सक्रिय होती है, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। नक्सलवाद के संदर्भ में जो परिणाम आज देश देख रहा है, वह केन्द्र और राज्य सरकारों के संकल्पित प्रयासों का ही फल है। जो बस्तर कभी लाल आतंक का प्रमुख गढ़ माना जाता था, वहां अब स्थायी शांति अपना आधार मज़बूत कर रही है। हिंसा का खेल खेलने वाले नक्सली चौतरफा सरकारी प्रयासों के चलते या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या कार्रवाई में ढेर हो रहे हैं। दूसरी ओर, जिन अंदरूनी इलाकों तक दशकों तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी थी, वहां आज सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं वास्तविक रूप ले रही हैं। पिछली उदासीन सरकारों और स्वार्थी माओवादियों ने जिन आदिवासियों को छला और लोकतंत्र से दूर रखा, वही समुदाय आज विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहा है। भले ही नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा हो, लेकिन इसके दशकों पुराने घाव बेहद गहरे हैं। सैकड़ों जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्या, विकास से पूरी पीढ़ियों को वंचित रखना और भय का वातावरण

ये सब नक्सलवाद की भयावह विरासत रही है। 2000 के दशक की शुरुआत में इसकी ताकत चरम पर थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे देश की "सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती" बताया, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों और संकल्प के अभाव में कांग्रेस सरकारें इस खतरे पर निर्णायक प्रहार नहीं कर सकीं। उस दौर में बस्तर से लेकर राजनांदगांव, गरियाबंद और कवर्धा तक आतंक की जड़ें फैल चुकी थीं। नक्सलियों का लक्ष्य दंतेवाड़ा से दिल्ली तक लाल झंडा फहराने का था, जिसे अर्बन नक्सल नेटवर्क से भी समर्थन मिलता था। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इस गंभीर खतरे को नज़रअंदाज़ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 जिले माओवादी आतंक की चपेट में आ गए और विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके विपरीत, आज मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से समझा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को उनके हाल पर छोड़कर देश पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकता। मजबूत इच्छा शक्ति और कठोर कार्रवाई के परिणाम आज सामने हैं। आज बस्तर ही नहीं पूरा दंडाकारण्य क्षेत्र विकास का नया अध्याय लिखने को आतुर है। यह क्षेत्र भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा है, बस्तर में रामपाल गांव, रामाराम मंदिर (सुकमा), राकसहाड़ा और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी भगवान राम से संबंधित हैं। नक्सलवाद के खग्रास ग्रहण से अब बस्तर मुक्त हो रहा है। अब एक बार फिर यहां भगवान राम का गौरव स्थापित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय सरकार यहां राम राज्य स्थापित के लिए संकल्पित है। यही फर्क है एक तरफ इच्छा शक्ति वाली सरकार और दूसरी तरफ उदासीन शासन की नाकामी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का विपक्ष भी इस सफलता को नकारात्मक चश्मे से देखने में लगा है। कुछ नेता यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर में उद्योगपतियों के लिए जमीन तैयार करने हेतु नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट

यह विडंबना है कि जब तक देश में कथित डिजिटल अरेस्ट के नाम पर अनुमानित तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक ठगी की जा चुकी है, कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बड़ी मुहिम शुरू हो पा रही है। वह भी सरकार के बजाय शीर्ष अदालत की पहल पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर गंभीर चिंता जताते हुए सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह अन्य साइबर अपराधों की जांच बाद में करे, डिजिटल अरेस्ट की जांच को अपनी प्राथमिकता बनाए। कोर्ट ने केंद्रीय बैंक से पूछा है कि क्या एआई की मदद से साइबर ठगों के खाते फ्रीज हो सकते हैं? कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि यदि किसी गंभीर डिजिटल अपराध का दायरा भारत से बाहर की सीमा में हो तो वह इंटरपोल की मदद ले सकती है। दुखद है कि साइबर अरेस्ट के मामलों में सबसे अधिक निशाना बुजुर्गों को ही बनाया जाता है, जिन्हें डिजिटल लेन–देन की गंभीर जानकारी नहीं होती। बुजुर्गों को निशाना बनाने का यह प्रतिशत 78 से 82 फीसदी बताया जाता है। कई जगह यह प्रतिशत 99 फीसदी तक है। वहीं जनवरी से अप्रैल 2024 में साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के 46 फीसदी मामलों के तार म्यांमार,कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जुड़े रहे हैं। निस्संदेह, हाल के वर्षों में डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराध के सबसे कुटिल रूप में बनकर उभरी है। यह अपराध न केवल देश की वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिये, बल्कि कानून प्रवर्तन तंत्र में जनता के विश्वास के लिये भी बड़ा खतरा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन घोटालों की देशव्यापी जांच सीबीआई को सौंपने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय समय के अनुरूप सार्थक हस्तक्षेप है। इसी क्रम में कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में अपराधों की जांच के लिये सीबीआई को सहमति दें। दरअसल, न्यायालय ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि साइबर अपराधी राज्यों की सीमाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर टुकड़ों–टुकड़ों में जांच सीमा–पार के साइबर अपराधियों के नेटवर्क को बढ़ावा देती है।

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई शुरू

सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर बनाने का दिया आदेश

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए राज्य के हर मंडल में निरुद्ध केंद्र बनाने के आदेश जारी कर दिये हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरी शासी निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की विस्तृत सूची बनाने के निर्देश दिये हैं। यह सूची आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त को सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया

कि कार्ययोजना के तहत पहले चरण में पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस आयुक्त को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान चिह्नित किये गये लोगों को रखने के लिए खास निरुद्ध केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हर मंडल में निरुद्ध केंद्र बनाने के निर्देश दिये।

इसके बाद प्रशासनिक तंत्र ने त्वरित कार्रवाई शुरू की है। कई जिलों में सत्यापन, दस्तावेजीकरण और क्षेत्रीय आकलन के कार्य शुरू किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने 22 नवंबर को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे और कहा था कि घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी हिरासत केंद्र बनाए जाएं। उन्होंने कहा था कि कानून एवं व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं हैं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को इन निरुद्ध केंद्रों में रखा जाएगा और जरूरी सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें वहीं रखा जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि निरुद्ध केंद्रों में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के मुताबिक उनके देशों में वापस भेजा जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अधिकारी पुलिस टीम के साथ झुग्गियों में पहुंचकर जांच कर रहे है, वहां के निवासियों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड समेत अन्य कागजात देखे जा रहे हैं। संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच भी की जा रही है। ऐसे में जो व्यक्ति घुसपैठिया मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी निश्चित हो गई है।

उम्मीद पोर्टल का समय बढ़ाने की मांग, पीएम मोदी को लिखा पत्र

मौलाना सैफ बोले, वेबसाइट क्रैश, समय बढ़ाना जरूरी

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने उम्मीद पोर्टल की सर्विस ठप होने

पर चिंता जताई। मौलाना ने पीएम मोदी और अल्पसंख्यक केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा। मौलाना ने कहा कि पिछले कई दिनों से उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन है जिसकी वजह से लोग चाह कर भी अपनी संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए सरकार को पोर्टल पर वक्फ संपत्ति दर्ज करने कि समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। मौलाना ने कहा कि हमारे पास उम्मीद पोर्टल से संबंधित लगातार शिकायतें आ रही हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं कि इसकी पूरी वेबसाइट हैंग हो गई है। लोग घंटों बैठे रहते हैं और एक भी संपत्ति ऑनलाइन नहीं चढ़ पाती। ऐसा लगता है की साइड क्रैश हो गई है और कई दिनों से काम नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। हमने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री को पत्र लिखकर मांग किया है कि अगर सरकार वक्फ हित में काम कर रही है तो अंतिम तिथि 5 दिसम्बर को बढ़ाया जाए। मौलाना ने कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक दिक्कत हो रही है जहां इंटरनेट सही काम नहीं करता। इन्होंने कहा कि अगर कुछ समय और मिल जाएगा तो उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में लोगों के अंदर जागरूकता और जानकारी नहीं थी बाद में जब लोग जागरूक हुए तो पोर्टल ठप हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जनहित और वक्फ हित में अंतिम तारीख जरूर बढ़ाए। मौलान ने पूरे भारत के वक्फ अध्यक्षों से अपील किया है कि डेलीगेशन बनाकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मुलाकात करके अपनी समय बढ़ाने की मांग करें।

संक्षिप्त

संपत्ति का ब्योरा नहीं तो प्रमोशन भी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारियों को सख्त निर्देश

8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर लटकी तलवार

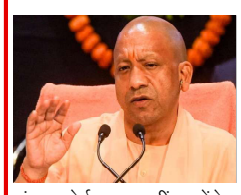

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब करने वालों की जेब और संपत्ति दोनों पर सरकार की नजर रहेगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी 31 जनवरी 2026 तक अपनी चल–अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं डालेंगे, उनका प्रमोशन पदोन्नति हमेशा के लिए रुक जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विभागाध्यक्षों को कड़े लहजे में आदेश जारी कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 से होने वाली डीपीसी यानि विभागीय पदोन्नति समिति में उन कर्मचारियों का नाम तक नहीं लिया जाएगा जिन्होंने संपत्ति का ब्योरा नहीं भरा होगा।प्रदेश में कुल 8 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। सरकार ने पहले भी कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन हजारों कर्मचारी अभी तक संपत्ति का ब्योरा नहीं दे रहे।अब सरकार ने आखिरी चेतावनी दे दी है।31 दिसंबर 2025 तक अर्जित की गई सारी संपत्ति घर, प्लॉट, दुकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, निवेश आदि का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा। पोर्टल 1 जनवरी 2026 से खुल जाएगा। आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 रात 12 बजे तक,इसके बाद डीपीसी में नाम नहीं आएगा। सरकार के मुताबिक जिन कर्मचारियों को नियम के अनुसार छूट मिली हुई है जैसे कुछ खास कैटेगरी, उन्हें ही इसमें राहत मिलेगी,बाकी किसी को माफी नहीं।

लूट के विरोध में महिला की गला घोंटकर हत्या, घर में बिखरा सामान

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित यशोदपुरम सेक्टर–1 में उस समय सनसनी फैल गई, जब 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला नीलमा श्रीवास्तव की लाश उनके घर में मिली। पुलिस के अनुसार, लूट के इरादे से आए बदमाशों ने विरोध करने पर महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। कमरे में अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान इध र–उधर बिखरा पड़ा था। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। नीलमा श्रीवास्तव मकान नंबर 129 में अकेली रहती थीं। उनके पति रमेश श्रीवास्तव की 25 साल पहले मौत हो गई थी, जबकि बेटा विभोर (सिक्योरिटी गार्ड) की 2018 में बीमारी से मौत हो गई। बहू नम्रता मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपने पिता के पास रहती हैं। घर बहू के पिता ने रिटायरमेंट के बाद खरीदा था और बेटी को दिया था, जिसमें सास नीलमा रहती थीं। बुजुर्ग होने

पहले भी एक कबाड़ी वाला बातों में फंसाकर उनके सोने के कंगन ले गया था। बुधवार सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। गले पर चोट के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो रात करीब 2.30 बजे शॉल ओढ़े एक संदिग्ध युवक के घर में जाते हुए दिखाई दिया। उसके आधार पर तलाश तेज कर दी गई है। आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच में जुटी है।

रालोद कार्यालय में मनाई गई डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जयंती

सत्य, सादगी, राष्ट्रनिष्ठा और समर्पण की प्रतिमूर्ति थे डॉ राजेंद्र प्रसाद-रामाशीष

संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने की। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा कि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सत्य, सादगी, राष्ट्रनिष्ठा और समर्पण की प्रतिमूर्ति थे। देश के निर्माण में उनकी भूमिका अतुलनीय रही है। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए।राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने कभी पद को नहीं, कर्तव्य को प्राथमिकता दी। आज के युवाओं को चाहिए कि वे उनके आदर्शों को अपनाएँ और समाज में सेवा, ईमानदारी और एकता का संदेश फैलाएँ। प्रदेश म इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रमावती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, अंकुर सक्सेना आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रमुख सचिव गृह से भारतीय पुलिस सेवा 77 वे आर आर बैच के कैडर के 23 अधिकारियों ने भेंट की

संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है इसके तहत वर्तमान प्रदेश सरकार जीरो टालरेंस नीति पर लगातार कार्य कर रही है जिससे आम जन में पुलिस की छवि और अधिक बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र में आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करे। जनता की समस्याओं का निस्तारण पारदर्शिता से कराये। उन्होंने कहा कि आई0पी0एस0 अधिकारियो को अपने तैनाती स्थल पर छोटी–छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रमुख सचिव गृह आज अपने लोकभवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार मे उ0प्र0 कैडर के 77 वें आर आर के 23 प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों से भेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली एवं जन संवाद के माध्यम से आम जन नागरिकों में बेहतर छवि बनाने में कोई कसर न छोड़े। संजय प्रसाद ने प्रशिक्षु आई0पी0एस0 आधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी जन आकांक्षाओं की कसौटी पर भविष्य में खरा उतरे और पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक जनता का विश्वास प्राप्त करे। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रशिक्षु आई0पी0एस0 आधिकारी जनसुनवाई हेतु निर्धारित समय पर कार्यालय में बैठे और समस्याओं का निस्तारण कराये। जनसुनवाई के दौरान आगन्तुकों से विनम्र व्यवहार करे।

प्रमुख सचिव गृह से मिलने आये प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारी सर्व अभय राजेन्द्र, अंजना दहिया, अंकित बंसल, बजरंग प्रसाद, दिक्षा भोरिया, दिनेश गोदारा, ईश्वर लाल गुज्जर, सुमेधा मिलिंद, जयबिन्द कुमार गुप्ता, कनिष्क आर0 जामकर, मानशी, मो0 आफताब आलम, प्रदीप कुमार, प्रेमसुख दरिया, एस0 दीप्ती चौहान, समयक चौधरी, संचित शर्मा, सारिका चौधरी, श्लोक गौतम, सृष्टि जैन, शुभम जैन, सिमरन सिंह व विनय कुमार यादव है। इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, बी0डी0 पालसन तथा विशेष सचिव गृह राकेश कुमार मालपानी, महेन्द्र व मंजूलता सिंह के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

शराब पीने के विवाद में हुई थी महिला की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर इलाके के विशाल खंड में 1 दिसंबर को हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आस–पास के लोगों व संदिग्धों से पूछताछ की। मेनुअल इनपुट, आउटपुट सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आध ार पर बुधवार को दोनों आरोपियों को विनीत खंड सब्जी मंडी से दबोच लिया गया। आरोपियों की पहचान मूल निवासी कटरी जनपद कानपुर नगर हाल पता म्यारी सब्जी देवेन्द्र सिंह (24) और नयी कालोनी

कमलाबाद बरौली सैरपुर निवासी सूरज पाल (24) पुत्र राम स्वरुप पाल हाल पता पानी की टंकी विशाल खंड 2 गोमतीनगर के रूप में हुई। अभियुक्त देवेन्द्र ने पूछताछ करने पर बताया कि सोमवार रात 8 बजे अपने ई–रिक्शा से नवाबपुरवा पर देशी शराब की दुकान पर शराब लेने गया था। वहां महिला ने हाथ देकर रोका और ई रिक्शा में बैठ गई। रास्ते में हमने उससे शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। उसने कहा हमको शराब पिलाओगे, तो मैं साथ चलूंगी। यह बात मैंने अपने दोस्त सूरज को फोन पर बताया। सूरज ने कहा ठीक है, ले आओ। इस पर मैं उसे सूरज की झोपडी विशाल खंड 2 लेकर गया। हम तीनों ने शराब पी। इसके बाद पैसे मांगने लगी और हंगामा शुरू कर दिया। आसपास रिहायशी एरिया होने के कारण हम लोगों को गुस्सा आ गया। स्से में हम दोनों ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर पीछे रखे तख्ते में लड़ गया। वह वहीं बेहोश हो गयी। कुछ देर बाद वह नहीं उठी, तो हम लोग डर गये। हम लोग अधि ाक रात होने का इंतजार करने लगे। रात 3 बजे हिलाकर देखा तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। हम दोनों ने उसे सूरज के ई–रिक्शा में डाला और विशाल खंड के मकान के पास दीवार से सटा कर रख दिया। उसके बाद फरार हो गए। पूछताछ में देवेंद्र ने बताया रेलवे स्टेशन गोमती नगर के पास युवती मिली। जिसने मिठाई वाले चौराहे पर छोड़ने की बात कही। रास्ते में ही साथ में शराब पार्टी करने का प्लान हो गया। इसके बाद सहमति से संबंध भी बनाने की बात हुई थी। पैसे के विवाद में जब उसे धक्का दिया गया तो तख्त से उसका सिर लड़ गया। जिससे वो बेहोश हो गई। घबराकर उसे ई–रिक्शा में बैठ कर 200 मीटर दूर एक जगह बैठा दिया गया। उम्मीद थी जब होश आएगा तब वह घर चली जाएगी। हालांकि सुबह उसकी मौत की खबर से हम लोग घबराकर भाग गए।

केजीएमयू में 30 दिव्यांगों को मिली व्हीलचेयर, कुलपति ने बताया रोल मॉडल

संवाददाता

लखनऊ। दिव्यांग हमारे लिए बोझ नहीं, ये हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इनके अंदर गजब की लगन और अद्भुत क्षमता होती है। आलस त्याग कर आगे बढ़ने का इनके अंदर जबरदस्त जज्बा होता। जो हम सभी को देश और समाज सेवा की सीख देता है। ये हमारे रोल मॉडल है। ऐसे में हर दिव्यांग के प्रति हमेशा इज्जत और लगाव का भाव रखना चाहिए। ये कहना है केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद का। बुधवार को फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन (पीएमआर) विभाग में दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग समाज को नई दिशा देने का माद्दा भी रखते हैं। केजीएमयू के फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन (पीएमआर) विभाग के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी केजीएमयू कैंपस में बड़ा आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों के बीच खेलकूद की प्रतियोगिता भी हुई। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से पोस्टर प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। 30 से ज्यादा दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्बस, कैलिपर्स और व्हीलचेयर भी दी गई। कार्यक्रम में कुलपति भी मौजूद रही और उन्होंने खुद भी कई दिव्यांग बच्चों के मनोबल को बढ़ाया। डॉ.

अनिल ने बताया एक्सीडेंट से दिव्यांग होने वाले रोजाना तीन से चार मरीज यहां पहुंचते हैं। कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो पुराने होते हैं और जिन्हें अपना कृत्रिम अंग बदलवाना होता है। दूसरे वह होते हैं जिनकी सर्जरी हो गई चोट का घाव भरा नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए भी स्टंप बनाया जाता है। ऐसे मरीजों को भर्ती कर कर एक्सरसाइज कर के उन्हें ठीक किया जाता है।

इसके बाद उनका आर्टिफिशियल अंग बनाया जाता है। डॉ.अनिल कुमार गुप्ता के मुताबिक, साल में लगभग 150 से 200 आर्टिफिशियल लिंब बनाए जाते हैं। लगभग इतने ही पुराने मामले होते हैं। जिसमें मरीज अपना लिंब बदलवाने या नया करवाने आते हैं। 5 से 6 हजार आर्टिफिशियल लिंब ऐसे मरीजों के लिए बनते हैं जो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होते हैं। जिसमें सेब्रल पाल्सी, पोलियो और ट्रॉमा के केस शामिल हैं। बीकेटी के रहने वाले आठवीं पास दीपक ने बताया मैं पढ़ाई करता था पर अचानक से पैरों में दिक्कत हुई जिस कारण स्कूल जाना छूट गया। तब से लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहा हूं। दवाई पर चल रहा हूं। डॉक्टर ने बताया है कि मुझे जो बीमारी हुई है, इसका इलाज है और उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तब एक बार फिर से पढ़ाई शुरू कर सकूंगा। मैं आगे चलकर शिक्षक बनना चाहता हूं। दीपक की मां नीलम कहती हैं बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था। वह रोज स्कूल जाता था और अचानक दोनों पैरों में उसके अकड़न हुई फिर उसका चलना फिरना बंद हो गया। अब पूरी तरह से व्हीलचेयर पर है। शुरुआत में इलाज में थोड़ी लापरवाही हुई पर अब लगातार इलाज चल रहा है। केजीएमयू के डॉक्टरों ने कहा वह ठीक हो जाएगा। आज यहां आए थे तो व्हीलचेयर मिली है। बेटा बहुत खुश है।

गोशालाओं का नियमित निरीक्षण करें अधिकारी

गोशालाओं में बनी रहे गोवंश हेतु हरे चारे, ठंड से बचाव, तिरपाल, औषधियां, पेयजल आदि की पर्याप्त उपलब्धता

योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध- सिंह

संवाददाता

लखनऊ। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विगत एक सप्ताह में प्रदेश के सभी गोआश्रय स्थलों पर व्यवस्थाओं के संबंध में जनपदीय नोडल अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण और उनके द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण आख्या की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। अधिकारी नियमित रूप से गोशालाओं का निरीक्षण करते रहें। गोशालाओं में प्रकाश सोलर लाइट की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए। गोवंश हेतु हरे चारे, ठंड से बचाव, तिरपाल, औषधियां, पेयजल आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। प्रत्येक गोशाला पर सीसीटीवी क्रियाशील कराये जाए और वृहद गोसंरक्षण केन्द्रों पर ड्रोन के उपयोग की संभावनाओं पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु संचालित गोआश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन तथा संरक्षित गोवंश के भरण पोषण, पराली संग्रहण के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन तथा जनपदों में एलएसडी बीमारी के संक्रमण की रोकथाम नियंत्रण तथा दुग्ध समितियों के संचालन की स्थिति की मण्डलवार गहन समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जनपद अयोध्या में सभी गोआश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अधिकांश स्थलों पर पराली संग्रहण किया जा रहा है। बाराबंकी में संरक्षित गोवंशों के सापेक्ष भरण पोषण हेतु पर्याप्त मात्रा में भूसा, साइलेज, पशु आहार एवं हरा चारा तथा शीघ्र रूप से बचाव के उचित प्रबंध पाये गये है। कासगंज में हरे चारे उपलब्ध है व साइलेज की उपलब्धता नहीं है। अस्थायी गोआश्रय स्थल मण्डी समिति में अतिरिक्त शेड की आवश्यकता है। हापुड़ में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा गोआश्रय स्थलों का नियमित भ्रमण नहीं किया जा रहा, जिस कारण गोवंशों को प्रचुर मात्रा में हरा चारा, दाना, भूसा इत्यादि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है एवं अवशेष निराश्रित गोवंश यत्र तत्र विचरण करते दिखे। जनपद महराजगंज में गोआश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे संचालित नहीं पाये गये। कानपुर देहात में मैथा ब्लाक अंतर्गत गोआश्रय स्थलों में गोवंशों को हरा चारा नहीं खिलाया जा रहा है और अभिलेख पूर्ण नहीं पाये गये। जनपद प्रतापगढ़ में पशुआहार का टेण्डर नहीं हुआ है और गोआश्रय स्थलों पर साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गयी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि जहां कमी पाई गई है वहां निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल, रखरखाव को दुरूस्त किया जाए। ठंड से किसी गोवंश की मृत्यु न हो पशुचिकित्साधिकारी गौ आश्रयस्थल पर जाकर गोवंश के उत्तम स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं औषधि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुग्ध समितियां किसी भी दशा में बंद न होने पाए और उनका संचालन सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास श्री मुकेश मेश्राम ने मंत्री जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि गोआश्रय स्थलों पर सभी व्यवस्थाएं उनसे प्राप्त निर्देशानुसार सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि गोशालाओं पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए और गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव कार्य किया जाए। गोसंरक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी।बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 7560 निराश्रित गोआश्रय स्थल हैं, जिनमें 1235253 गोवंश संरक्षित हैं। मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत कुल सुपुर्द गोवंश 180919 हैं, जिनसे 114628 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।बैठक में पशुधन विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र पाण्डेय, पीसीडीएफ के एमडी वैभव श्रीवास्तव, दुग्ध आयुक्त के धनलक्ष्मी, विशेष सचिव दुग्ध राम सहाय यादव, पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉ मेमपाल सिंहउपस्थित थे।

अर्धसैनिक बल के जवान वीरता, साहस और देशभक्ति के प्रतीक-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों का बढ़ाया मनोबल, कहा–आप राष्ट्र की शान हैं

बीएनई

हल्द्वानी/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप मुख्यालय हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्धसैनिक बलों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक हर मोर्चे पर अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। तिरंगे की शान को बढ़ाने में इन वीर सपूतों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अर्द्धसैनिक बल के जवानों को वीरता, साहस और देश भक्ति का प्रतीक बताते हुए उन्हें राष्ट्र की शान बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए घोषणा की कि भविष्य में प्रेजिडेन्ट पुलिस मेडल–गैलेन्ट्री वीरता पदक से अलंकृत होने वाले अर्द्धसैनिक को एकमुश्त 05 लाख रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी, पूर्व अर्द्धसैनिक एवं अर्द्धसैनिक की वीर नारी, जिसके पास स्वयं की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, को उत्तराखण्ड राज्य में जीवनकाल में एक बार अचल सम्पत्ति क्रय किये जाने में स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, उत्तराखण्ड राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद् को क्रियाशील किया जायेगा और परिषद् के लिए पुलिस मुख्यालय में एक कार्यालय कक्ष आवंटित किया जायेगा, सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) एवं बड़े जिलों के जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) के एक–एक पद स्वीकृत किये जायेंगे, जिसमें पूर्व अर्द्धसैनिक संविदा में नियुक्त किये जायेंगे, जो स्वयं एक सैनिक परिवार से आते हैं और सैनिकों व उनके परिवारों की चुनौतियों को नजदीक से समझते हैं। शहीदों की शहादत की कोई कीमत नहीं हो सकती और राज्य सरकार का दायित्व है कि उनके परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों

अर्द्ध सैनिक बलों के बच्चे हैं, उनको शादी हेतु हमारे सैनिकों के भांति धनराशि प्रदान की जाएगी तथा मुख्यमंत्री ने सीजीएचएस भवन निर्माण हेतु तत्काल प्राथमिकता देते हुए भूमि चयन करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक कभी भी 'भूतपूर्व' नहीं होता, वह जीवनपर्यंत सैनिक ही रहता है। उन्होंने बताया कि वे और शहीदों के परिजनों के सम्मान हेतु अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रूपये किया है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से अलंकृत वीरों की पुरस्कार राशि एवं वार्षिक अनुदान में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। शहीदों की स्मृति में स्मारक एवं शहीद द्वार निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष 10 वीर बलिदानियों की स्मृति में नए स्मारकों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही शहीदों के परिजनों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की व्यवस्था भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सेना का आधुनिकीकरण तेजी से हुआ है। भारत आज रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनते हुए कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। 'ऑपरेशन सिंदूर' ने भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता को विश्व स्तर पर सिद्ध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध बसावट और अन्य गलत गतिविधियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है। 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराई गई है तथा 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा–रोधी कानून और भू–कानून लागू कर सामाजिक समरसता एवं आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड वीरभूमि भी है, और यहां की धरोहर, संस्कृति तथा परंपरा की रक्षा करना सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार "विकल्प रहित संकल्प" के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु निरंतर दृढ़ता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर मेयर हल्द्वानी गजराज सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक राम सिंह कैड़ा, दायित्व धारी डॉ. अनिल डब्बू, शंकर कोरंगा, रेनू अधिकारी, आई जी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीआईजी शंकर दत्त पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ मंजूनाथ टीसी, पूर्व अर्धसैनिक संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष एस.एस. कोटियाल, सेवानिवृत्त आईजी एम. एल. वर्मा, एच.आर. सिंह, भानु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एनसीएल सीडब्ल्यूएस ने सीएसआर के तहत स्कूली बच्चों को निःशुल्क जूते प्रदान किए

200 से अधिक बच्चों ने उठाया लाभ

बीएनई

सिंगरौली। एनसीएल की सभी परियोजना एवं इकाइयों द्वारा समय–समय पर सीएसआर के तहत स्थानीय परिक्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को एनसीएल की सीडब्ल्यूएस इकाई द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत शासकीय प्राथमिक पाठशाला, गोलाई बस्ती, जयन्त, शासकीय प्राथमिक पाठशाला, सेन्ट्रल वर्कशॉप और शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मुड़वानी, जयंत में विद्यार्थियों को निरू शुल्क जूतों का वितरण किया गया। एनसीएल सीडब्ल्यूएस द्वारा यह कार्य बढ़ती ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस दौरान लगभग 207 विद्यार्थियों ने वितरण का लाभ उठाया। इस अवसर पर परियोजना से नोडल अधिकारी (सीएसआर) एवं स्कूल के प्राचार्य तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि एनसीएल सीएसआर के तहत स्थानीय परिक्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास, पेय जल व आधारभूत ढांचे के निर्माण जैसे अनेक कार्य कर रही है।

कर्ज रिपोर्टों में गलतियां, क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ बढ़ीं शिकायतें

एजेंसी

नई दिल्ली। कर्ज रिपोर्टों में भारी गलतियां पाई गई हैं। इससे उधारकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। इसका पता इस बात से चलता है कि क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ तीन वर्षों में शिकायतें चार गुना बढ़ गई हैं। यह तेज उछाल ऐसे समय में आया है जब भारत के वित्तीय लोकपाल की ओर से निपटाई जाने वाली शिकायतों में बैंकों, एनबीएफसी और डिजिटल भुगतान कंपनियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओंबुड्समैन पर सालाना रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई। इसके अनुसार, क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ शिकायतें 2022–23 में 1,039 से बढ़कर 2023–24 में 3,847 और 2024–25 में 4,585 हो गईं। यह सभी विनियमित संस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि है। इनमें से कई शिकायतें ऋण और अग्रिमों से संबंधित हैं। यह क्रेडिट सूचना कंपनियों से जुड़ी सभी शिकायतों का 84 फीसदी से अधिक हिस्सा हैं। लोकपाल के पास दर्ज कुल शिकायतें 2024–25 में बढ़कर 2.95 लाख तक पहुंच गईं। ये आंकड़े वित्तीय क्षेत्र को बढ़ते ग्राहक आधार, अधिक रिफाइंड उत्पादों और सेवा सटीकता की बढ़ती अपेक्षाओं से जूझते हुए दर्शाते हैं। बैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिलने का क्रम जारी है। वित्त वर्ष 2024–25 में इनके खिलाफ 2,41,601 शिकायतें मिलीं। इसी तरह, जमा खातों से संबंधित मामले सभी शिकायतों में 20.63 फीसदी तक पहुंच गए। क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतें दो वर्षों में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़कर 17. 16 फीसदी तक पहुंच गईं। एटीएम और डेबिट कार्ड में आई भारी कमी हालांकि, कुछ श्रेणियों में थोड़ी राहत देखी गई। एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें 14.56 फीसदी से घटकर 7.47 फीसदी हो गईं।

संगठित क्षेत्र की नौकरियों में 23 फीसदी की बढ़त, गैर–आईटी क्षेत्रों में बढ़ी मांग

एजेंसी

नई दिल्ली। शिक्षा, रियल एस्टेट, आतिथ्य और यात्रा व बीमा जैसे गैर–आईटी क्षेत्रों में मांग बढ़ने से नवंबर में संगठित क्षेत्र की नौकरियों में 23 फीसदी की तेजी देखी गई है। नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स के अनुसार, दिवाली के आगे बढ़ने से अक्तूबर में नियुक्तियों में 9 फीसदी गिरावट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में आईटी नियुक्तियां स्थिर रहीं। गैर–आईटी क्षेत्रों में नियुक्तियों में ठोस वृद्धि रही। उच्च मूल्य वाली भूमिकाओं (20 लाख रुपये सालाना) व यूनिकॉर्न की नियुक्तियों में क्रमशरू 38 और 35 फीसदी की वृद्धि हुई। यूनिकॉर्न में ई–कॉमर्स कंपनियों की संख्या 27 फीसदी रही।

इनमें सर्वाधिक भर्तियां

शिक्षा : 44 फीसदी

रियल एस्टेट : 40 फीसदी

आतिथ्य/यात्रा : 40 प्रतिशत

बीमा : 36 प्रतिशत

इनमें रही तेज वृद्धि

चेन्नई : 49 फीसदी

हैदराबाद : 41 फीसदी

दिल्ली–एनसीआर : 41 फीसदी

अहमदाबाद : 41 फीसदी

आईटी यूनिकॉर्न में 16 फीसदी की तेजी रही। प्रवेश स्तर पर नियुक्तियों में 30 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसमें छोटे शहरों की प्रमुख भूमिका रही। 13–16 वर्ष के अनुभव वाले वरिष्ठ समूहों में यूनिकॉर्न की नियुक्तियों में 50 फीसदी वृद्धि रही। कुल भर्तियों में जयपुर में 31 फीसदी की तेजी रही। मुंबई और बंगलूरू जैसे प्रमुख महानगरीय केंद्रों में क्रमशः 29 प्रतिशत व 26 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

संक्षिप्त

रेपो दर घटने की उम्मीद, बजाज ऑटो को 34.74 करोड़ का टैक्स नोटिस

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक बुधवार से शुरू होगी। फैसला शुक्रवार को आएगा। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। फिलहाल यह दर 5.5 फीसदी पर है। अक्तूबर में मुद्रास्फीति घटकर दशक के निचले स्तर 0.25 प्रतिशत पर आ गई है। इससे दरों में कटौती की भरपूर गुंजाइश मानी जा रही है। बजाज ऑटो को 34.74 करोड़ का टैक्स नोटिस बजाज ऑटो को आपूर्ति किए गए कलपुर्जों के गलत वर्गीकरण के कारण उत्तराखंड विभाग से 3.47 करोड़ रुपये जुर्माने के साथ 34.74 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। बजाज ऑटो ने मंगलवार को कहा, योग्यता के आधार पर उसका मामला काफी मजबूत है, क्योंकि वह लंबे समय से पुर्जों और सहायक उपकरणों का सही ढंग से वर्गीकरण कर रही है। इसलिए वह इसके खिलाफ अपील दायर करेगी।

आरबीआई की एमपीसी बैठक शुरू, मजबूत GDP और घटती महंगाई के बीच रेपो दर पर रहेगी नजर

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक आज से शुरू हुई। एमपीसी के सदस्य जीडीपी वृद्धि और महंगाई के नवीनतम आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति की भावी दिशा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नीतिगत नतीजों की घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार सुबह 10 बजे करेंगे। इस समय भारत का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब भारत का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है और महंगाई में तेजी से गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही, जुलाई–सितंबर की अवधि में जीडीपी का आंकड़ा 8.2 प्रतिशत पर रहा। वहीं महंगाई रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (डवैच्) के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई अक्तूबर 2025 में तेजी से गिरकर 0. 25 प्रतिशत पर आ जाएगी। आरबीआई रेपो दर को रख सकता है स्थिर–रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक इस बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रख सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आरबीआई दिसंबर 2025 में रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रखेगा। साथ ही रुख को तटस्थ बनाए रखने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि महंगाई में और कमी आने की उम्मीद है और यह आरबीआई के अपने अनुमानों से भी नीचे आ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार संभावित ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश के बावजूद, आरबीआई आगामी नीति समीक्षा में सतर्कता बरत सकता है। मजबूत आर्थिक गतिविधि की अवधि के दौरान ब्याज दरों में कटौती नहीं करता इस बीच वर्तमान स्थिति को देखते हुए केयरएज रेटिंग्स के एमडी और ग्रुप सीईओ मेहुल पंड्या ने बताया कि मजबूत जीडीपी वृद्धि और कई वर्षों से कम महंगाई दोनों ही ब्याज गर निर्णयों के लिए विपरित संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों घटनाक्रम ब्याज दर के दृष्टिकोण से परस्पर विरोधी ताकतें हैं। केंद्रीय बैंक आमतौर पर जीडीपी वृद्धि द्वारा दर्शाई गई मजबूत आर्थिक गतिविधि की अवधि के दौरान ब्याज दरों में कटौती नहीं करते हैं। साथ ही, केंद्रीय बैंक आमतौर पर कम महंगाई वाले माहौल में ब्याज दरों में कटौती करके प्रतिक्रिया देते हैं।

रुपये में रिकॉर्ड गिरावट कांग्रेस आक्रामक, वीडियो साझा कर प्रधानमंत्री को उनकी ही बात याद दिलाई

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान रुपया 9 पैसे टूटकर 90.05 प्रति डॉलर पर खुला, जो अब तक का इसका सबसे निचला स्तर है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का पुराना बयान सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसमें मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, ऐसे में भारत वैश्विक व्यापार में टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी इस बोझ को सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है।

जिस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी इस बोझ को सह नहीं पाएंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार. .. रुपया 90 के पार इस हफ्ते रुपये का हाल भारतीय रुपया सोमवार को विदेशी मुद्रा बाजार में बड़ी गिरावट के साथ अपने नए सर्वकालिक निचले स्तर पर फिसल गया। शुरुआती कारोबार में रुपये में दबाव बढ़ा और यह डॉलर के मुकाबले 34 पैसे गिरकर 89.79 के रिकॉर्ड लो पर आया। वहीं रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपये प्रति डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने के बाद 42 पैसे की गिरावट के साथ 89.95 रुपये (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ।

टैरिफ का फायदा उठाकर चीन बढ़ा रहा दबदबा, भारत के निर्यात में 12.6% गिरावट, कई सेक्टर हुए प्रभावित

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर अमेरिका में लगे टैरिफ का फायदा चीन उठा रहा है। इससे देश के कई प्रमुख बाजारों में चीनी वस्तुओं का दबदबा बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हुई लेकिन इसकी अगुवाई स्मार्टफोन ने की, जिसके निर्यात मूल्य में 2.4 अरब डॉलर की तेजी आई है। अधिकांश अन्य प्रमुख निर्यात श्रेणियों में तेजी से गिरावट आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के टैरिफ दबाव और आक्रामक चीनी प्रतिस्पर्धा का यह मेल भारत की निर्यात क्षमता को कमजोर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स ही एकमात्र बेहतर क्षेत्र है। स्मार्टफोन ने इस क्षेत्र के निर्यात में 60 फीसदी का भारी योगदान दिया। इसमें अक्तूबर में आईफोन का योगदान 1.6 अरब डॉलर था। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह वास्तविक वृद्धि नहीं है। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि अक्तूबर में भारत के व्यापारिक निर्यात में भारी कमी देखी गई। अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों में भी इसी तरह की गिरावट दर्ज की गई। यह कई वर्षों में पहली बार हुआ है। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, लंबे समय में पहली बार भारत की शीर्ष दस निर्यात श्रेणियों में सामूहिक रूप से गिरावट आई है।

निर्यात में 19 फीसदी की वृद्धि जरूर

फराह खान ने बोमन ईरानी को दी जन्मदिन की बधाई, शेयर की प्यारी तस्वीर

एजेंसी

मशहूर फिल्म निर्माता–निर्देशक फराह खान ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और अभिनेता बोमन ईरानी को जन्मदिन की बधाई दी। इस साल उन्होंने अपना के 66वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर फराह ने बोमन के लिए एक प्यारा पोस्ट शेयर किया है। फराह का पोस्ट बोमन का जन्मदिन 2 दिसंबर को था। फराह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बोमन को गले लगाते हुए एक बेहद ही क्यूट तस्वीर शेयर की और लिखा, श्मेरे प्यारे और बहुत प्रतिभाशाली दोस्त बोमन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिर्फ प्यार और बहुत सारा प्यार। दोनों ने साल 2012 में आई फिल्म शशिरीन फरहाद की तो निकल पड़ीश में साथ काम किया था। यह फराह की बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म थी।

बोमेन का वर्कफ्रंट बोमन जल्द ही प्रभास की फिल्म श्द राजा साबश में नजर आएंगे। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। बोमन के जन्मदिन पर फिल्म की टीम ने उनका नया पोस्टर जारी किया, जिसमें वे एक मनोचिकित्सक और रहस्य सुलझाने वाले किरदार में हैं। फिल्म के निर्माताओं ने लिखा, श्वह शख्स जो सच और रहस्य के बीच खड़ा है३ टीम रुजीमत्वैंइ बोमन ईरानी को जन्मदिन की बहुत–बहुत बधाई देती है। द राजा साब की कास्ट द राजा साबश एक हॉरर–कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में प्रभास के अलावा मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, संजय दत्त और बोमेन ईरानी समेत कई कलाकार हैं। यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी।

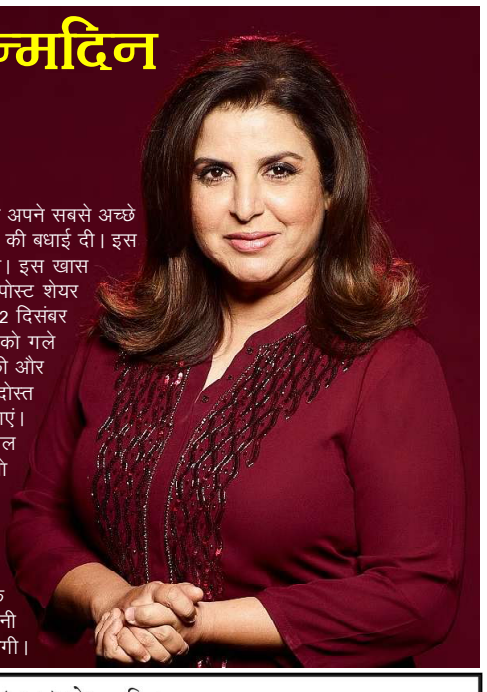

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743